सत्यमेव जयते

गृह मंत्रालय
भारत सरकार

देश प्रथम

केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह, बॉर्डर पर जवानों को प्रोत्साहित करते हुए

अधिदेश

गृह मंत्रालय, आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। गृह मंत्रालय के अधिदेश में सीमा प्रबंधन, केन्द्र–राज्य सम्बंध, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, आपदा प्रबंधन, विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम, वीज़ा और नागरिकता सम्बंधी मुद्दे शामिल हैं। केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल का प्रबंधन, गृह मंत्रालय के प्रमुख अधिदेश के निर्वहन से सम्बंधित उसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक है।

गृह मंत्रालय, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों, जम्मू एवं कश्मीर एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति की लगातार मॉनीटरिंग करता है, खुफिया जानकारी साझा करता है, राज्य सरकारों को लोक व्यवस्था बनाए रखने तथा अपने नागरिकों, विशेषकर, महिलाओं एवं अन्य संवेदनशील समूहों की सुरक्षा एवं संरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए जनशक्ति एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। गृह मंत्रालय राज्यों को अपने पुलिस बलों को आधुनिक बनाने, उन्हें मजबूत करने एवं प्रशिक्षित करने में भी मदद करता है।

...आतंकवाद को गैर–कानूनी ठहराया जाना चाहिए... मानवता में विश्वास करने वालों को एक एकजुट होकर इस समस्या के विरुद्ध एक स्वर में आवाज उठानी चाहिए...

श्री नरेन्द्र मोदी
भारत के प्रधानमंत्री

... पिछले 48 महीनों में भारत अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के मामले में एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा है और उसे दूसरे राष्ट्रों का सम्मान मिल रहा है। पड़ोसी देश सहित कोई भी देश हमारे देश की सुरक्षा को अस्थिर नहीं कर सकता है क्योंकि सरकार सभी मोर्चों पर सुरक्षा को मजबूत कर रही है...हमारे सुरक्षा बल कारगर ढंग से अपना कार्य कर रहे हैं और वे कभी भी हम भारतीयों का सर झुकने नहीं देंगे...

श्री राजनाथ सिंह
भारत के गृह मंत्री

NATIONAL INVESTIGATION AGENCY
GOVERNMENT OF INDIA
NIA
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण मुख्यालय
का
उदघाटन
श्री राजनाथ सिंह
माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार
के कर–कमलों द्वारा
श्री हंसराज गंगाराम अहीर
गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार
श्री किरेन रिजिजू
गृह राज्य मत्री, भारत सरकार
श्री शरद कुमार, महानिदेशक
एवम्
श्री योगेश चन्द्र मोदी, भा॰ पु॰ से॰, विशेष कार्याधिकारी
की उपस्थिति में
दिनाँक 10 अक्टूबर, 2017
यथा मगलवार, कार्तिक कृष्णपक्ष पंचमी तिथि, शक संवत् 1939 को सम्पन्न हुआ।
कार्यान्वयन एजेंसी :
एन बी सी सी
NBCC

सुरक्षा सबसे पहले

सुरक्षा परिदृश्य में स्पष्ट सुधार

पिछले 48 माह में बहु-आयामी रणनीति अपनाई

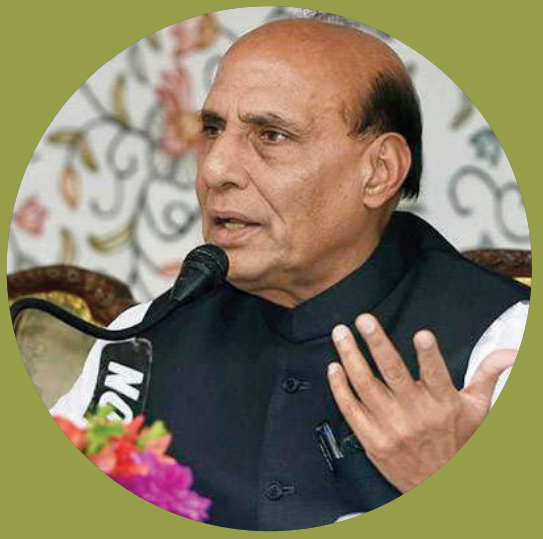

सतत कार्रवाई

उग्रवादियों एवं विद्रोहियों के विरुद्ध

राहत और पुनर्वास

पीड़ितों को मुहैया

बातचीत

भारत के संविधान का अनुपालन करने वालो के साथ

सीमा एवं तटीय सुरक्षा

सुदृढ़ की गई

अधिकार और हकदारियां

स्थानीय समुदायों के लिए सुनिश्चित

राज्य सुरक्षा तंत्र

को मजबूती

विकास कार्यों में तेजी

वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों, पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू एवं कश्मीर, अंतर्राष्ट्रीय बार्डर तथा तटीय क्षेत्र में

पूर्वोत्तर में

63% ↓
विद्रोही घटनाओं में कमी

83% ↓
सिविलियन मौतों में कमी

40% ↓
सुरक्षा बलों के हताहतों में कमी

आईएसआईएस के आरम्भिक खतरे को नियंत्रित किया गया

वामपंथी उग्रवाद के भौगोलिक विस्तार में कमी

2013 **126** → 2018 **90**
जिले

36.6% ↓ हिंसा की घटनाएँ

55.5% ↓ मृत्यु

जम्मू एवं कश्मीर में मारे गए उग्रवादियों की संख्या

2010-2013	2014-2017
471	619

1. तालमेल से कार्य करते हुए केन्द्रीय एवं राज्य एजेंसियों द्वारा 113 आईएसआईएस समर्थकों को गिरफ्तार किया गया

2. आईएसआईएस एवं अंसार-उल-उमाह (एयूयू) को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया

3. इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) को गैर-कानूनी संगठन घोषित किया गया

4. एनआईए की तीन नई शाखाओं को कोलकाता, रायपुर एवं जम्मू में शुरू किया गया

5. इंडियन मुजाहिदीन के आधार को नष्ट किया गया – वर्ष 2013 में दिलकुशनगर, हैदराबाद में धमाके कराने के दोषी इंडियन मुजाहिदीन के 5 कार्यकर्ताओं को मृत्यु दंड की सजा दी गई

6 युद्ध छेड़ने के लिए आपराधिक षड़यंत्र हेतु यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के शीर्ष नेतृत्व को 7–10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई

7 जम्मू एवं कश्मीर में आतंकवादियों को धन मुहैया कराने के मामले का पता लगाया गयाः एनआईए द्वारा बारह अभियुक्तों को चार्जशीट किया गया

8 प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सिमी के शीर्ष नेतृत्व सहित 18 कार्यकर्ताओं को केरल में आतंकवाद प्रशिक्षण कैम्प आयोजित करने के कारण सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई

9 कारगर उपाय करके नक्सलियों, विद्रोहियों, अलगाववादियों तथा आतंकवादी समूहों के लिए धन के प्रवाह को रोका गया

10 जाली भारतीय करेंसी नोट्स की जब्तियों एवं बरामदगियों के रिकॉर्डों के ऑनलाइन रख-रखाव हेतु वेब आधारित सॉफ्टवेयर चालू किया गया

पूर्वोत्तर

पूर्वोत्तर क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति में उल्लेखनीय सुधार

85%
कमी
विद्रोही घटनाओं में

96%
कमी
वर्ष 1997 से
सुरक्षा बल एवं
सिविलियन हताहतों में

एएफएसपीए
आर्म्ड फोर्सेज़ (स्पेशल पावर्स) एक्ट का ऑपरेशन

मेघालय
से हटाया गया

अरुणाचल प्रदेश में
कम किया गया

पुलिस स्थापना और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास

₹213 करोड़

तिरप, चांगलांग एवं लोंगडिंग
अरुणाचल प्रदेश में

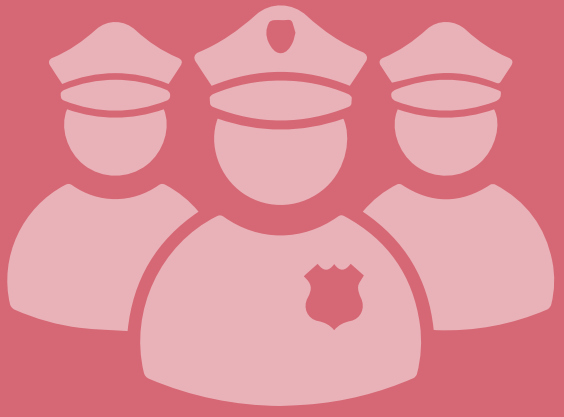

वामपंथी उग्रवाद

वामपंथी उग्रवाद की समस्या से निपटने के लिए गृह मंत्री द्वारा दिया गया नया प्रचालनात्मक सिद्धांत 'समाधान'

एस	स्मार्ट पुलिसिंग एवं नेतृत्व
ए	आक्रमक रणनीति
एम	मोटिवेशन एवं प्रशिक्षण
ए	एक्शनेबल इंटैलिजैन्स
ड	मुख्य परफोरमेंस इंडिकेटर के माध्यम से विकास
एच	हारनेस करना – विकास एवं सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का
ए	एक्शन प्लान – प्रत्येक क्षेत्र के लिए
एन	नो एक्सेस – वित्त पोषण पर

वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) में भारी कमी

भौगोलिक विस्तार में कमी

पुलिस थानों से हिंसा की रिपोर्टिंग में कमी

328 ⇩ **291**

वर्ष 2013 — वर्ष 2017

हिंसा में कमी

(2010 - 2013) बनाम (2014 - 2017)

2428 ⇩ **1081**

एलडब्ल्यूई से होने वाली मौतों में कमी

6524 ⇩ **4136**

हिंसा की घटनाओं में कमी

445 ⇧ **510**

एलडब्ल्यूई कॉडरों के उन्मूलन में तेजी

1387 ⇧ **3373**

वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) कॉडरों के आत्मसमर्पण में वृद्धि

2018 में मई तक, 119 वामपंथी उग्रवादियों का सफाया किया गया

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को मुख्यधारा से जोड़ा गया

रोड रिक्वायरमेंट प्लान (आरआरपी)

आरआरपी –I

4544 किमी
का सड़क निर्माण पूरा किया गया

अनुमानित लागत
₹ 8593 करोड़

8 राज्यों के वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 38 जिलों में कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए वामपंथी उग्रवाद के प्रभाव वाले प्रमुख क्षेत्रों में पिछले 4 वर्षों में 1615 किमी सड़कों का निर्माण किया गया

आरआरपी –II

44 जिलों में
5412 किमी
सड़कें

₹ 11725 करोड़

4066 किमी सड़कों के लिए राज्यों को पहले ही मंजूरी दे दी गई है

दूरसंचार

मोबाइल टावर्स

2329
मोबाइल टावर्स लगाए गए

4072
टावरों का निर्माण चरण –II में किया जाना है

सीआरपीएफ

बस्तरिया बटालियन का गठन

743 आदिवासी युवक

242 महिलाएँ

छत्तीसगढ़ के वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित चार जिलों से नियुक्त किए गए

■ सुरक्षा सम्बंधी व्यय (एसआरई) स्कीम के अंतर्गत सहायता

2010-2011 से 2013-2014	बनाम	2014-2015 से 2017-2018
₹ 875 करोड़		₹ 1121 करोड़

■ वर्ष 2017-18 से आबंटन को अगले 3 वर्षों के लिए बढ़ाकर ₹ 445 करोड़ प्रति वर्ष किया गया

फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन स्कीम

327 निर्माण पूरा किया गया 2014-2018

393 का निर्माण पूरा किया गया बनाम 400 स्वीकृत

250 अतिरिक्त मंजूरी

वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित 35 जिलों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता

सार्वजनिक मूलभूत सुविधाओं तथा सेवाओं में भारी कमियों को दूर करने की नई पहल

₹ 3000 करोड़

₹1000 करोड़ रुपए वार्षिक

वित्तीय समावेशन

450 बैंक शाखाएँ खोली गईं

1123 एटीएम खोले गए

डाकघर

1789 मंजूर किये गए

565 खोले गए

अनुग्रह राशि का भुगतान बढ़ाया गया

₹ 3 लाख से ⬆ 20 लाख

राशि बढ़ाई गई, (मारे गए सुरक्षा कर्मियों के परिवार के लिए)

नए प्रावधान

- सुरक्षा कार्मिकों को हुई अशक्तता के लिए मुआवज़ा
- संपत्ति के नुकसान के लिए मुआवज़ा

पुनः आरम्भ की गई विशेष अवसंरचना योजना

₹1048 करोड़

जम्मू एवं कश्मीर

प्रधानमंत्री का विकास पैकेज

₹ 80,068 करोड़

विकास एवं समावेशन के माध्यम से प्रोफ़ाइल में बदलाव

आईआईटी ■ आईआईएम ■ दो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ■ दो स्मार्ट सिटीज़ ■ स्वास्थ्य देखभाल सम्बंधी बुनियादी सेवाओं में वृद्धि ■ प्रमुख सड़कों और नई टनल्स का विकास करके हर मौसम में कनेक्टिविटी ■ जम्मू एवं श्रीनगर शहरों में सेमी रिंग रोडस् ■ विद्युत – जेनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ■ झेलम और इसकी सहायक नदियों में सुधार कार्य ■ डल और नगीन झीलों का संरक्षण ■ पर्यटन ■ खेलकूद ■ बागवानी विकास ■ युवाओं के लिए रोज़गार ■ पाक अधिकृत जम्मू एवं कश्मीर तथा छम्ब से आए विस्थापित व्यक्तियों, कश्मीरी और जम्मू प्रवासियों को सहायता

"वतन को जानो": युवाओं के लिए भारत दर्शन कार्यक्रम

2011-2014 / 535 जम्मू एवं कश्मीर के युवाओं ने भारत के विभिन्न भागों का भ्रमण किया

2015-2018 / 2800 जम्मू एवं कश्मीर के युवाओं ने भारत के विभिन्न भागों का भ्रमण किया

सब्सिडाइज्ड हेलिकाप्टर सेवाएँ

जम्मू एवं कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के दूर दराज़ के 20 सेक्टरों में शुरू की गई

सुरक्षा सम्बंधी व्यय

जम्मू एवं कश्मीर राज्य को अधिक प्रतिपूर्ति

₹ 1765 करोड़
2010 – 2014

₹ 3496 करोड़
2014 – 2018

आतंकवादी हिंसा में शहीद हुए जम्मू एवं कश्मीर पुलिस कार्मिकों के लिए अनुग्रह राशि को बढ़ाकर

₹10 लाख (2013) ₹30 लाख (2017)

जम्मू एवं कश्मीर पुलिस में 25,474 विशेष पुलिस अधिकारियों के मानदेय को बढ़ाकर

₹3000 ₹6000

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा चलाया गया सिविक एक्शन प्रोग्राम

जम्मू एवं कश्मीर के 4,600 युवकों को शामिल करके केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा 300 फुटबाल टीम बनाई गईं

शांति वार्ता

जम्मू एवं कश्मीर राज्य में निर्वाचित प्रतिनिधियों, विभिन्न संगठनों और सम्बंधित व्यक्तियों के साथ वार्ता शुरू करने और उसे आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार के प्रतिनिधि की नियुक्ति की गई

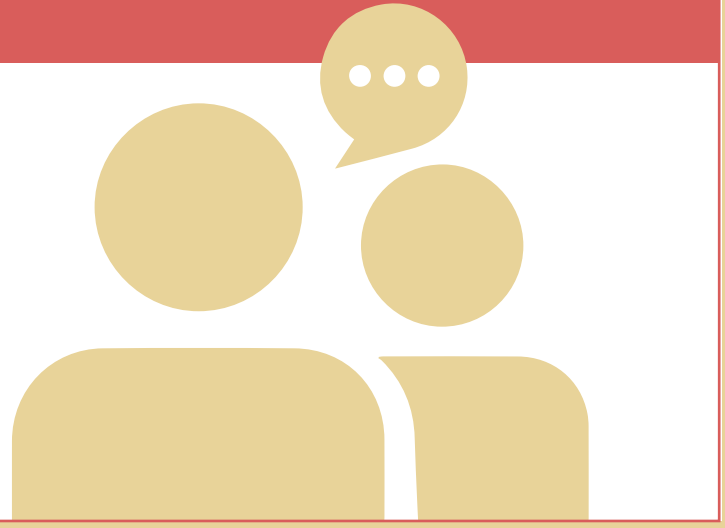

भर्ती, कौशल विकास एवं रोज़गार

जम्मू एवं कश्मीर से सीधी भर्ती

3882
केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में

7302
भारतीय सेना में

7698
जम्मू एवं कश्मीर पुलिस में विशेष पुलिस अधिकारी

4690
पांच नई इंडिया रिजर्व बटालियनें

3000
कश्मीरी प्रवासियों को राज्य सरकार की अतिरिक्त नौकरियाँ देने की प्रक्रिया चल रही है

2014
जम्मू एवं कश्मीर पुलिस की दो नई सीमा बटालियनों के लिए भर्ती का अनुमोदन प्रदान किया गया

कौशल विकास

उड़ान स्कीम

18,174
ग्रेजुएट्स तथा डिप्लोमा होल्डर्स को नौकरियों का ऑफर दिया गया

हिमायत स्कीम

56,829
स्कूल और कॉलेज ड्रॉप आउट्स को नौकरियों का ऑफर दिया गया

महिला सशक्तिकरण

4,780
कुपवाड़ा में महिलाओं को स्व-भरणपोषण का प्रशिक्षण दिया गया

कश्मीरी तथा जम्मू प्रवासियों के लिए राहत और पुनर्वास

प्रतिमाह प्रति परिवार + राशन

22,000
कश्मीरी प्रवासी परिवार
₹ 6600 ⬆ ₹ 10000

1,054
जम्मू प्रवासी परिवार
₹ 1600 ⬆ ₹ 10000

नई पहलें

पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर एवं छम्ब से विस्थापित व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता

₹ 5.5 लाख प्रति परिवार

वित्तीय सहायता 12,051 लाभार्थियों के आधार लिंक बैंक खातों में

₹ 578 करोड़

की राशि संवितरित की गई

सीमा पार से होने वाली गोलाबारी से पीड़ित व्यक्तियों के लिए राहत

₹416 करोड़

1431 कम्युनिटी बंकर्स और 13029 इंडीविजुअल बंकरों के निर्माण के लिए

₹05 लाख

मारे गए प्रति नागरिक के लिए मुआवजे का अनुमोदन

एनडीआरएफ दरों पर मुआवजा

मकानों, फसलों और पशुधन की हानि के लिए अनुमोदित

अवैध ड्रग तस्करी को रोकना

	मई 2010 से अप्रैल 2014	मई 2014 से अप्रैल 2018
दर्ज मामले	752	1,053
अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की गई	12	18
अवैध प्रयोगशालाओं का पता लगाया	13	16
पकड़ी गई नशीली दवाएँ (कोकेन, एटीएस, मेथाकेलोन, मेफेड्रोन और गांजा)	18,124 कि.ग्रा.	67,298 कि.ग्रा.
जब्त की गई हैरोइन	903 कि.ग्रा.	1,822 कि.ग्रा.

स्मार्ट पुलिस

पुलिस आधुनिकीकरण

नई स्कीम

पुलिस आधुनिकीकरण के लिए तैयार एक नई व्यापक अम्ब्रेला योजना

दो वर्टिकल्स

पुलिस बलों का आधुनिकीकरण (एमपीएफ)

सुरक्षा सम्बंधी व्यय (एसआरई)

कुल परिव्यय

₹ 25,000 करोड़

2018-2020

संस्थाओं की स्थापना और उनका अपग्रडेशन

अमरावती में नई हाई-टैक स्टेट फोरेंसिक साईंस लैब की स्थापना

₹ 152 करोड़

जयपुर में सरदार पटेल ग्लोबल सेंटर फॉर सिक्योरिटी, कांउटर टेररिज़्म एंड एंटी इनसरजेंसी की स्थापना

₹ 165 करोड़

अहमदाबाद में गुजरात फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय का उन्नयन

₹ 180 करोड़

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) का सशक्तिकरण – प्रक्रियाओं में बदलाव

1. तीन चरण की प्रक्रिया को दो चरण में बदल कर उपकरणों की खरीद में तेज़ी लाई गई
2. उपकरणों की तकनीकी विशेषताओं को अंतिम रूप देने का अधिकार सीएपीएफ को दिया गया
3. उपकरणों के आवर्तक परीक्षण से बचने के लिये तकनीकी मूल्यांकन की वैधता को 1–2 वर्ष किया गया
4. नई इकाइयों/प्रतिष्ठानों हेतु मोटर वाहनों की खरीद के लिए सीएपीएफ की वित्तीय शक्तियों को ₹20 करोड़ तक बढ़ाया गया
5. बेकार घोषित किये गये वाहनों के स्थान पर नये वाहन खरीदने पर लगे विशिष्ट प्रतिबंध को हटाया गया
6. शस्त्रों तथा उपकरणों के आयात के लिए आयात लाइसेंस से छूट प्रदान की गई

अभियोजन तंत्र को सुदृढ़ बनाना:
नई केन्द्रीय फोरेंसिक साईंस प्रयोगशालाएँ

तीन

गुवाहाटी, पुणे और भोपाल में नई केन्द्रीय फोरेंसिक साईंस प्रयोगशालाओं (सीएफएसएल) के भवनों का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है

छह

फोरेंसिक डीएनए और डिजिटल फोरेंसिक सहित नए फोरेंसिक डिविजनों की स्थापना

सीएपीएफ को अधिकार दिया गया

सीएपीएफ की प्रचालन क्षमताएँ बढ़ाने के लिए उन्हें शस्त्रों, गोला बारूद, मशीनों, उपकरणों और आईटी सिस्टम्स की खरीद के लिए प्राधिकृत किया गया

अनुबंध स्वीकृत

₹3090 करोड़

अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम (सीसीटीएनएस) की स्थापना

परिणाम	2014	31 मार्च, 2018
थाने जिनमें सीसीटीएनएस सॉफ्टवेयर लगा है	73%	99.5%
सीसीटीएनएस से जोड़े गए थाने	73%	94%
सीसीटीएनएस के उपयोग से रजिस्टर की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट	45 लाख	184 लाख

डिजिटल पुलिस पोर्टल

नागरिकों के लिए सेवाएँ

- अपराध की सूचना दें
- व्यक्तियों के सत्यापन के लिए अनुरोध
- राज्य पुलिस नागरिक पोर्टल

पुलिस के लिए सेवाएँ

- राष्ट्रीय अपराध और आपराधिक डाटाबेस पर खोज
- उन्नत खोज और विश्लेषण
- अपराध सांख्यिकी रिपोर्टें

राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के नागरिक पोर्टल

2014-15

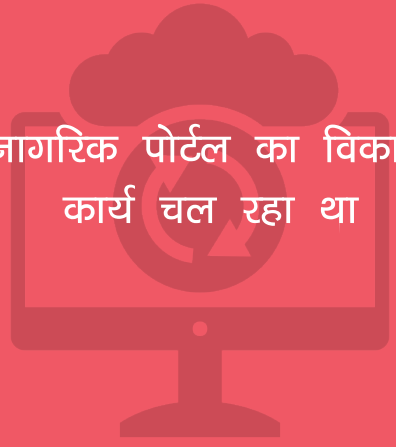

नागरिक पोर्टल का विकास कार्य चल रहा था

2017-18

पोर्टल विकास कार्य पूरा हुआ

नागरिकों को ऑनलाइन पुलिस सेवाएँ प्रदान करने के

लिए सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने पोर्टल लॉन्च किए गए

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र नागरिक पोर्टल का उपयोग करके

नागरिकों द्वारा 3 लाख शिकायतें दर्ज की गईं

नौकरी, रोज़गार, पासपोर्ट आदि के सम्बंध में

13 लाख जाँच अनुरोध प्राप्त हुए

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ)

57264

पदों पर भर्ती की गई

2 महिला बटालियनों का सीआरपीएफ में गठन

54953

पदों पर भर्ती की योजना

21

महिला कम्पनियों

के गठन को एसएसबी में मंजूरी दी गई

28

एनएसजी रीजनल हब

आंतकरोधी क्षमता को बढ़ाने के लिए 4 हब कार्यरत किए गए चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और मुम्बई। अहमदाबाद में पांचवें की स्वीकृति

दंगों/दंगों जैसे हालातों को रोकने के लिए 5 जीडी बटालियनों को 5 रेपिड एक्शन फोर्स बटालियनों में बदला गया

अनुमोदित

06 बीएसएफ बटालियन

40 इंडिया रिज़र्व बटालियन

35 सीएपीएफ बटालियनों का गठन किया गया

04 सीएपीएफ बटालियनों का गठन किया जा रहा है

2015–16 में बीएसएफ के एयर विंग बेड़े में 08 नए एमआई – 17 वी5 हैलीकॉप्टर शामिल किए गए

कल्याणकारी पहलें

सीएपीऐफ कार्मिकों के लिए आवासीय सुविधा

13,072 मकान | **113** बैरक | **68** भू–स्थल — के लिये — **₹ 3091** करोड़

- कार्रवाई के दौरान सीएपीएफ के घायल कार्मिकों की अस्पताल में ईलाज की अवधि को ''ड्यूटी पर'' मानने के लिए अनुमोदन दिया गया
- राष्ट्र के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) तथा असम राइफल्स एवं सीपीओ के कार्मिकों के निकटतम सम्बंधी (एनओके) के सम्बंध में 'कार्रवाई के दौरान हताहत प्रमाणपत्र' प्रदान करने का अनुमोदन किया गया
- सीएपीएफ कार्मिकों के लिए हवाई कोरियर सेवा के फेरों में वृद्धि की गई, #22000 प्रति मास
- राष्ट्र के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले सीएपीएफ के कार्मिकों के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करने हेतु छात्रवृत्तियाँ दी गईं

11288 छात्रवृत्तियाँ सीएपीएफ के कार्मिकों के बच्चों को

478 छात्रवृत्तियाँ शहीद सैनिकों के बच्चों के लिए

'भारत के वीर' केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के निकटम परिजन (एनओके) के लिए एक अभिनव पहल है, जिसमें लोग उनके वेल्फेयर के लिए या 'भारत के वीर कॉर्पस' में अंशदान कर सकते हैं

• गृह मंत्रालय शिकायत ऐप

ऐप सीएपीएफ जवानों को गृह मंत्रालय से जोड़ता है

• 'हिम्मत ऐप' में संशोधन करके उसे 06.02.2018 को 'हिम्मत प्लस' के रूप में लॉन्च किया गया

सीमाओं को सुरक्षित रखना

भारत–पाकिस्तान, भारत–चीन तथा भारत–बांग्लादेश सीमा पर

सीमा चौकसी बढ़ाना : ₹6209 करोड़

247 किमी
लम्बी बाड़ बनाई गई

785 किमी
लम्बे क्षेत्र पर फ्लड लाईटें लगाई गईं

589 किमी
लम्बी सीमावर्ती सड़कों का निर्माण

168
सीमा जाँच चौकियों की स्थापना की गई

व्यापक सीमा प्रबंधन सिस्टम

इसमें शामिल होंगे:
रडार ■ डे ऐंड नाइट विज़न कैमरा ■ सैंसर ■ माइक्रो एयरोस्टेट ■ कमांड ऐंड कंट्रोल सेंटर

योजना के तहत पहले 2 सेक्टर
- जम्मू 10 किमी
- धुबरी 61 किमी

दोनों कार्य जल्द पूरे किए जाएँगे

समुद्र तट क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ाना

194 तटीय पुलिस स्टेशनों को निम्नलिखित अपेक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ चालू किया गया है:

- **204** नाव
- **97** चैकपोस्ट
- **58** आउट पोस्ट
- **30** बैरक
- **284** चौपहिए वाहन
- **554** दुपहिए वाहन

26 समुद्र द्वीपों के समग्र विकास की योजना

अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में 16 द्वीप
लक्षद्वीप में 10 द्वीप

निम्नलिखित पर जोर

- हवाई, समुद्री, सड़क एवं वेब कनेक्टिविटी बेहतर करना
- अच्छी गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध कराना
- विद्युत आपूर्ति बढ़ाना
- द्वीपवासियों को अधिकतम लाभ प्रदान करना
- पर्यटन आधारित आर्थिक विकास एवं रोजगार को बढ़ावा देना

10 तटीय पुलिस थाने

अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में किए जाने वाले अपराधों से निपटने के लिए अधिसूचित

राष्ट्रीय तटीय पुलिस व्यवस्था अकादमी (एनएसीपी)

मोजप गाँव, जिला देवभूमि, गुजरात में स्वीकृत।
जुलाई 2018 से पाठ्यक्रम की शुरूआत

सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम

₹3905 करोड़

की राशि वर्ष 2014 – 18 के दौरान 17 सीमावर्ती राज्यों को दी गई

₹126 करोड़

की राशि व्यापक विकास हेतु 61 आदर्श गाँवों के लिए दी गई

एकीकृत जाँच चौकियों को संचालित किया गया

- यात्री एवं कार्गो टर्मिनलः रक्सोल एवं जोगबनी
- कार्गो टर्मिनलः पैट्रापोल
- यात्री टर्मिनलः मोरेह

लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग पर व्यापार तथा यात्रियों के बेहतर आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए

34

महिला सशक्तिकरण

महिलाओं से सम्बंधित पहलें

₹200 करोड़

केन्द्रीय पीड़ित मुआवजा कोष योजना (सीवीसीएफ) के तहत निर्भया कोष से राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को एक-बारगी अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता जारी की गई

₹1 लाख

दिनांक 09.11.2016 से प्रारम्भ की गई केन्द्रीय पीड़ित मुआवजा कोष योजना (सीवीसीएफ) के तहत पहले से लागू मुआवजे के अलावा तेजाब हमला पीड़िताओं को पीएमएनआरएफ से सहायता

33%
महिलाओं के लिए आरक्षण

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा दिल्ली पुलिस सहित सभी संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस बलों में कांस्टेबल से उपनिरीक्षक तक के अराजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती में महिलाओं के लिए राज्यों को 33% आरक्षण करने की सलाह दी गई

महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराध के लिए 48 जाँच यूनिट्स स्थापित की गईं

केन्द्र सरकार के 50% आर्थिक वित्तपोषण से वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान महिलाओं के प्रति अपराध के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा ऐसे और यूनिट्स की स्थापना की गई

महिलाओं की सुरक्षा सम्बंधी परियोजना

दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी निगरानी की शुरुआत की गई

दिल्ली में 60 सलाहकारों को लिया गया

संकट में फंसी महिलाओं के परामर्श के लिए निर्भया कोष के तहत

मानव तस्करी को नियंत्रित करना

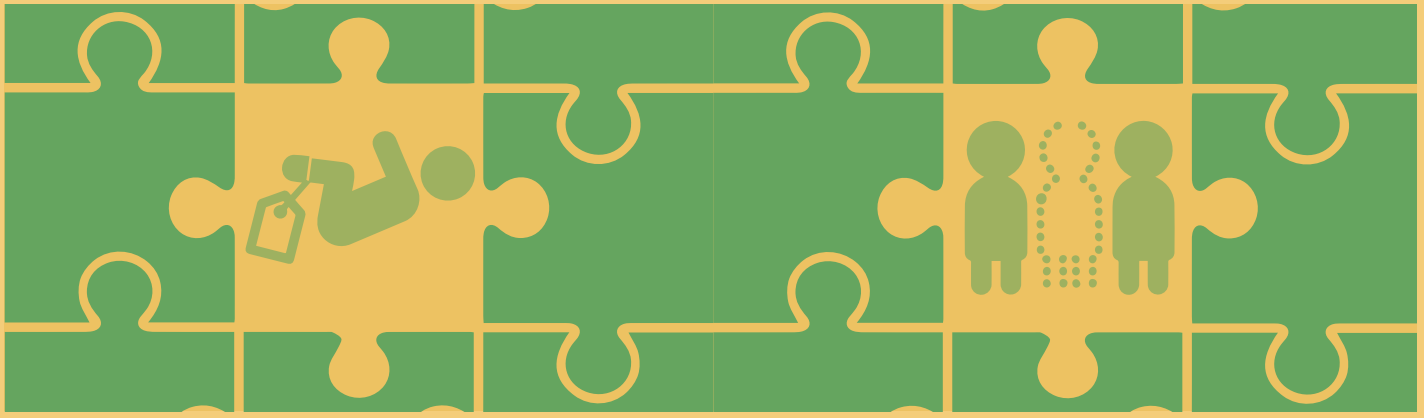

ऑपरेशन स्माइल' / 'ऑपरेशन मुस्कान'

की शुरूआत गुमशुदा बच्चों को मुक्त कराने तथा उन्हें उनके माँ–बाप से मिलवाने के लिए की गई

मानव तस्करी की रोकथाम के लिए द्विपक्षीय सहयोग

सहयोग हेतु भारत तथा बांग्लादेश (जून 2015), भारत तथा यूएई (जनवरी, 2017) तथा भारत एवं कम्बोडिया (जनवरी, 2018) के बीच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए

जेल सुधार

आदर्श जेल नियमावली

को तैयार किया गया तथा इसे राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में परिचालित किया गया ताकि देश में जेलों के प्रशासन तथा कैदियों के प्रबंधन को शासित करने वाले कानून, नियमों एवं विनियमों में आधारभूत एकरूपता लाई जा सके

संशोधित दिशानिर्देश

अनुसंधान करने, डाक्युमेंटरी बनाने तथा कैदियों का साक्षात्कार लेने आदि के उद्देश्यों से व्यक्तियों/ स्वयंसेवी संगठनों/ कंपनियों/ प्रेस को जेलों के दौरे की अनुमति प्रदान करने के लिए संशोधित दिशानिर्देश बनाए गए

न्याय

दंड विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2018

कड़ी सजा का प्रावधान

- 12 वर्ष से कम आयु की लड़कियों का बलात्कार करने वाले व्यक्तियों के लिए मृत्यदंड
- 16 वर्ष से कम आयु की लड़कियों का बलात्कार करने वाले सामूहिक बलात्काारियों के लिए उम्रकैद
- 16 वर्ष से कम आयु की लड़कियों का बलात्कार करने वाले व्यक्तियों को अग्रिम जमानत प्रदान नहीं

जाँच एवं ट्रायल

- बलात्कार से जुड़े सभी मामलों की जाँच एवं अभियोजन सम्बंधी कारवाई को अनिवार्य रूप से 2 माह के भीतर पूरा करना होगा
- बलात्कार से जुड़े मामलों सम्बंधी अपील का उच्च न्यायालयों द्वारा 6 माह के भीतर निपटान किया जाना होगा
- बलात्कार से जुड़े मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना
- बलात्कार से जुड़े मामलों के लिए प्रत्येक राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में विशेष फोरेंसिक लैब
- यौन अपराधियों का राष्ट्रीय डाटा बेस तथा प्रोफ़ाइल तैयार किया जाएगा

निभाए गए वायदे

शत्रु सम्पत्ति

शत्रु सम्पत्ति अधिनियम में संशोधन के परिणामस्वरूप सरकार को ₹1 लाख करोड़ से अधिक की शत्रु सम्पत्ति को सुरक्षित कर अपने नियंत्रण में लेने का अधिकार

ऐन्क्लेव (बस्तियों) की अदला-बदली

111
भारतीय ऐन्क्लेव (बस्तियों)

51
बांग्लादेशी ऐन्क्लेव (बस्तियों)

की अदला-बदली की गई

₹1006 करोड़

वापस लौटने वाले व्यक्तियों को बसाने के लिए भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित परियोजना को लागू किया जा रहा है

स्वतंत्रता सैनानी पेंशन

अगस्त, 2016 में स्वतंत्रता सैनानियों तथा उनके आश्रितों की पेंशन में 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई तथा इसे केन्द्रीय सरकार के मंहगाई भत्ते से लिंक कर दिया गया है

नागरिकों का पंजीकरण

1 असम के लिए नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी)

भारत सरकार असम राज्य में एनआरसी 1952 को अद्यतन बनाने का कार्य कर रही है

पार्ट ड्राफ्ट एनआरसी 1951, जिसमें 1.9 करोड़ व्यक्तियों का नाम है, को दिनांक 31.12.2017 को प्रकाशित किया गया तथा शेष 1.38 करोड़ व्यक्तियों के सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है

2 राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर

घरेलू डेटाबेस

120.41 करोड़

व्यक्तियों का

तैयार किया

40

संघ राज्य क्षेत्र

1984 के सिक्ख-विरोधी दंगे

बढ़ा हुआ मुआवजा

₹05 लाख

1984 के सिक्ख-विरोधी दंगों के दौरान मारे गए सभी 3325 व्यक्तियों के नजदीकी रिश्तेदारों का मुआवजा बढ़ा

आगे की जाँच पड़ताल

सिक्ख-विरोधी दंगों से जुड़े मामलों की जाँच तीन सदस्यीय विशेष जाँच दल (एसआईटी) द्वारा पुनः शुरू की गई है

सौर उर्जा — दीव

6 मेगावाट सौर ऊर्जा

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा बिजली परियोजना का शुभारम्भ किया गया

3 मेगावाट सौर ऊर्जा

माननीय गृहमंत्री द्वारा परियोजना का शुभारम्भ किया गया

दीव ऐसा प्रथम जिला है जो अपनी माँग के अनुरूप नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है

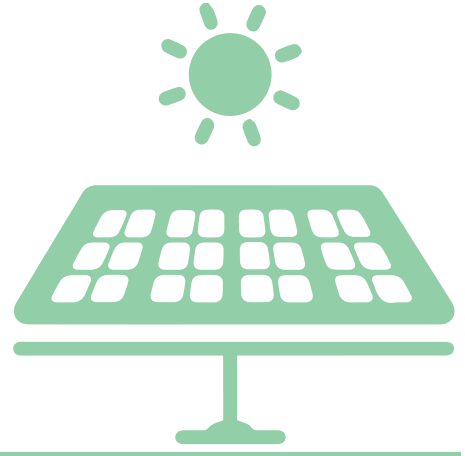

चंडीगढ़ में **21** सोलर एमडब्ल्यूपी क्षमता के संयत्रों की स्थापना

260 सरकारी भवनों/स्थलों में 18 एमडब्ल्यूपी तथा 189 निजी भवनों/स्थलों पर 3 एमडब्ल्यूपी की स्थापना

बेहतर क्नेक्टिविटी

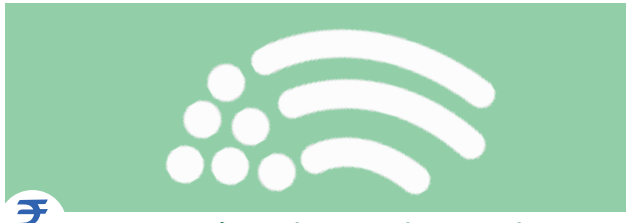

₹ 880 करोड़ की सबमरीन ऑप्टीकल फाइबर केबल परियोजना लागू की गई, पोर्टब्लेयर तथा 5 द्वीपसमूहों को देश के मुख्य भाग से जोड़ने के लिए

₹ 1748 करोड़ की राशि संघ राज्य क्षेत्र अंडमान एवं निकोबार में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु प्रदान की गई

पोर्ट ब्लेयर तथा अंडमान एवं निकोबार के दक्षिणी द्वीपसमूहों के बीच चार्टर्ड जलयान एम. वी. कोरल क्वीन की सेवाएँ शुरू की गईं

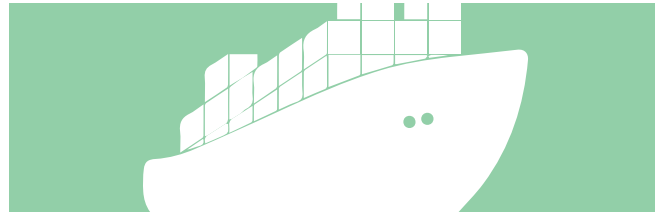

अंडमान एवं निकोबार में अंतर द्वीपसमूह एवं तटीय क्षेत्रों के लिए 400 टन के कार्गो जलयान एमवी चुगलम की सेवाओं को शुरू किया गया

42

लक्षद्वीप फ्लीट में 400 यात्रियों के क्षमता वाले दो जलयानों तथा दो 800 मीट्रिक टन के कार्गो बार्जेज़ को शामिल किया गया

लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र में यात्री–सह–कार्गो जलयानों, यात्री जलयानों, ऑयल बार्जेज़ तथा एलपीजी कैरियर सहित 16 जलयानों के अधिग्रहण हेतु 15 वर्षीय (2015–2030) भावी योजना का अनुमोदन

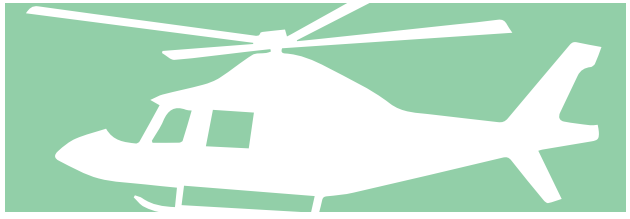

इंटर–आइलैंड एवं द्वीपसमूहों तथा देश के मुख्य भाग के बीच कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए लक्षद्वीप में अतिरिक्त हैलीकॉप्टरों का अनुमोदन किया गया

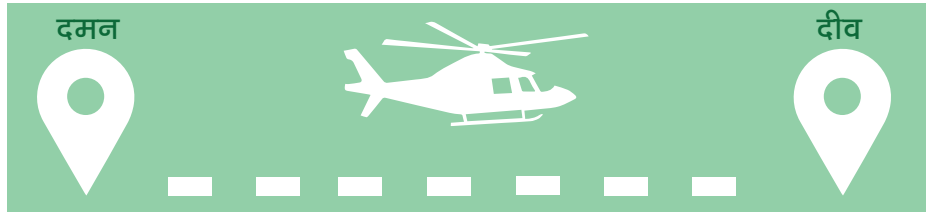

दमन एवं दीव के बीच हैलीकॉप्टर सेवा की शुरूआत की गई

संवर्धित विकास

सभी संघ राज्य क्षेत्र खुले में शौच से मुक्त हैं; पुदुचेरी जून 2018 तक खुले में शौच से मुक्त हो जाएगा

चंडीगढ़ तथा पुदुचेरी में पीडीएस में डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर को लागू किया गया

चंडीगढ़ तथा पुदुचेरी केरोसिन मुक्त संघ राज्य क्षेत्र हैं

सभी संघ राज्य क्षेत्रों में लाभार्थी–उन्मुखी सभी योजनाएँ डीबीटी (डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर) प्रणाली पर आधारित हैं

लक्षद्वीप में स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने के लिए 188 करोड़ रु. की लागत से 6 द्वीपसमूहों के लिए डिसेलीनाइजेशन प्लांट का अनुमोदन किया गया है

चंडीगढ़ में 96 किलोमीटर लम्बे साइकल ट्रैक का निर्माण कराया गया। 70 किलोमीटर का निर्माण कार्य प्रगति पर है

दमन में शैक्षणिक सत्र 2018–19 से इंजीनियरिंग कॉलेज का शुभारम्भ

दादरा एवं नगर हवेली, सिलवासा में 189 करोड़ रु. की लागत से मेडिकल कॉलेज की स्थापना किए जाने का अनुमोदन किया गया है

एमबीबीएस में सालाना 50 सीटों के इंटेक के साथ करायकल में जेआईपीएमईआर की शाखा का शुभारम्भ

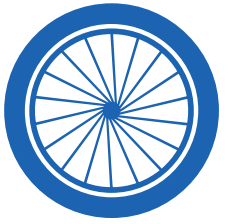

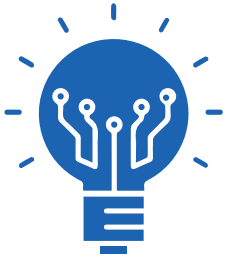

आपदा प्रबंध

आपदा से निपटने की तैयारी

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की क्षमता में वृद्धि

2 अतिरिक्त बटालियन

- उत्तर प्रदेश
- अरुणाचल प्रदेश

चरण–1

आंध्रप्रदेश और ओडिशा के राज्यों में राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (एनसीआरएमपी) शीघ्र पूर्ण होने की स्थिति में है

चरण–2

छह राज्यों (गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल) में कार्यान्वयन हो रहा है

₹ 4903 करोड़

46

एक प्रतिबद्धता के रूप में भारत को आपदा-रिज़िलिएंट बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा वर्ष 2016 में पहली राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एनडीएमपी) जारी की गई तथा इसे सेंडाई फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन ऑन डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन से जोड़ा गया

विभिन्न स्कीमों के माध्यम से राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों तथा आपदा के प्रति कमज़ोर समुदायों की क्षमता में वृद्धि की जा रही है

राहत सहायता में 2015 से काफी वृद्धि (रु. करोड़)

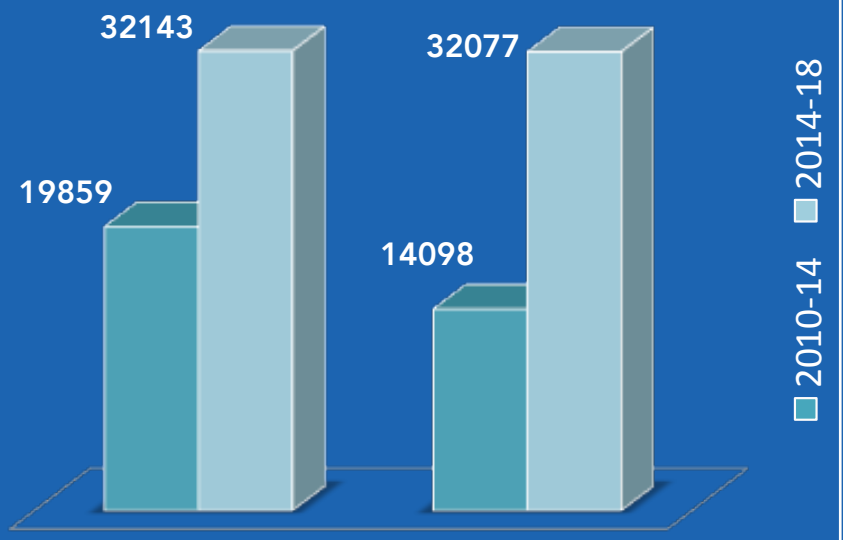

- मृत्यु पर अनुग्रह राशि में वृद्धि

₹ 1.5 लाख ↑ प्रति व्यक्ति ₹ 4 लाख

- कृषि सहायता में वृद्धि

↑ 50%

अंतर राज्य परिषद (आईएससी)

(आईएससी) और इसकी स्थायी समिति को दोबारा सक्रिय करना

- लगभग 10 वर्षों के अंतराल के बाद जुलाई 2016 में आईएससी की बैठक आयोजित की गई
- वर्ष 2005 के 12 वर्ष बाद आईएससी की स्थायी समिति की बैठक वर्ष 2017 में आयोजित की गई
- वर्ष 2017–18 के बीच आयोजित तीन बैठकों में, स्थायी समिति द्वारा केंन्द्र–राज्य सम्बंधों के बारे में पुंछी आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों (273) पर विचार किया गया
- स्थायी समिति की सिफारिशों को अंतिम निर्णय हेतु शीघ्र ही आईएससी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा

क्षेत्रीय परिषदें

- मई 2014 से क्षेत्रीय परिषदों की दस बैठकें आयोजित की गईं जबकि इससे पहले चार वर्षों के दौरान चार बैठकें आयोजित की गई थीं
- पिछले चार वर्षों के दौरान, क्षेत्रीय परिषदों की स्थायी समिति की पंद्रह बैठकें आयोजित की गईं जबकि इससे पहले चार वर्षों के दौरान पांच बैठकें आयोजित की गई थीं
- पिछले चार वर्षों के दौरान, इन बैठकों में कुल 406 मुद्दों का समाधान किया गया है

क्षेत्रीय परिषदें: अभूतपूर्व प्रगति

क्षेत्रीय परिषद और स्थायी समिति की बैठकों का चार्ट

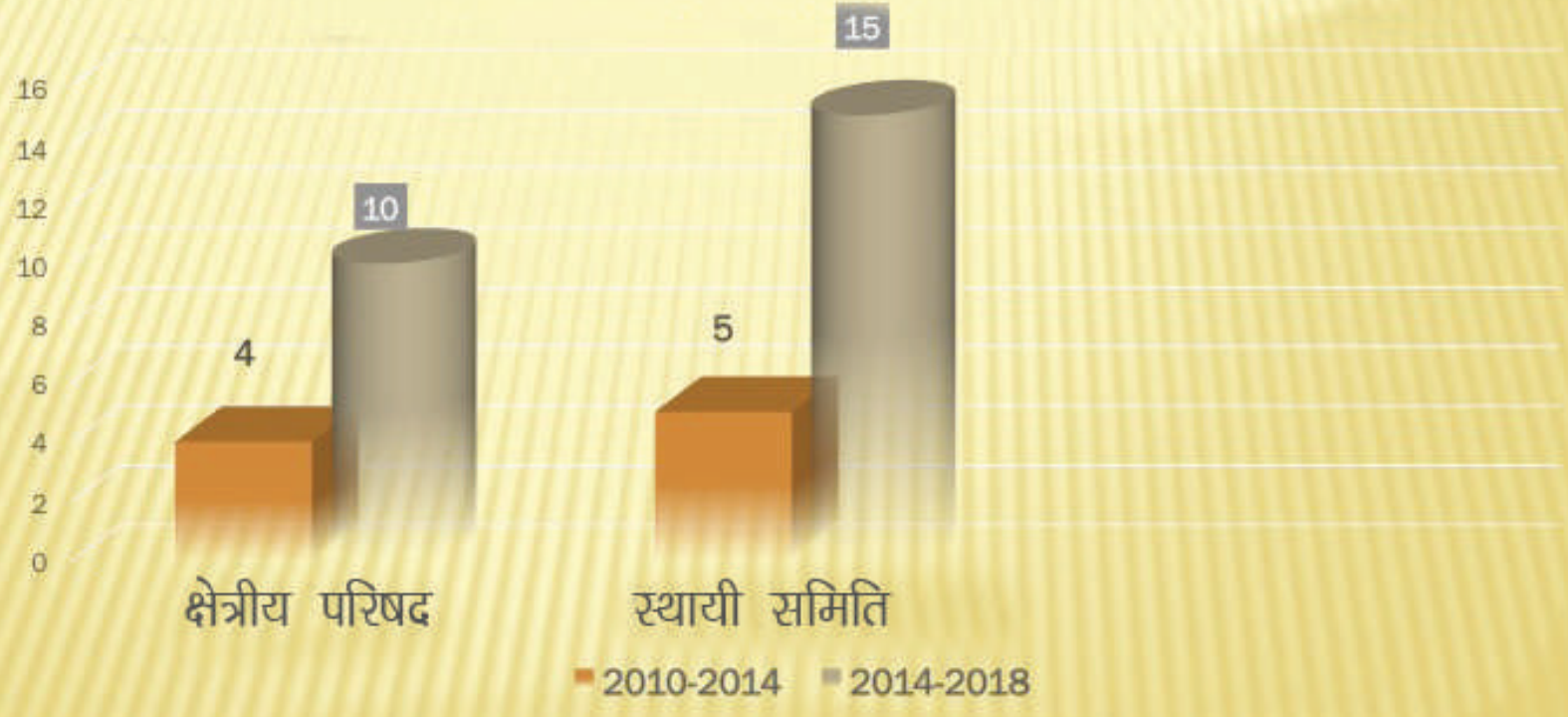

अवधि की गणना: मई से मई तक

ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस

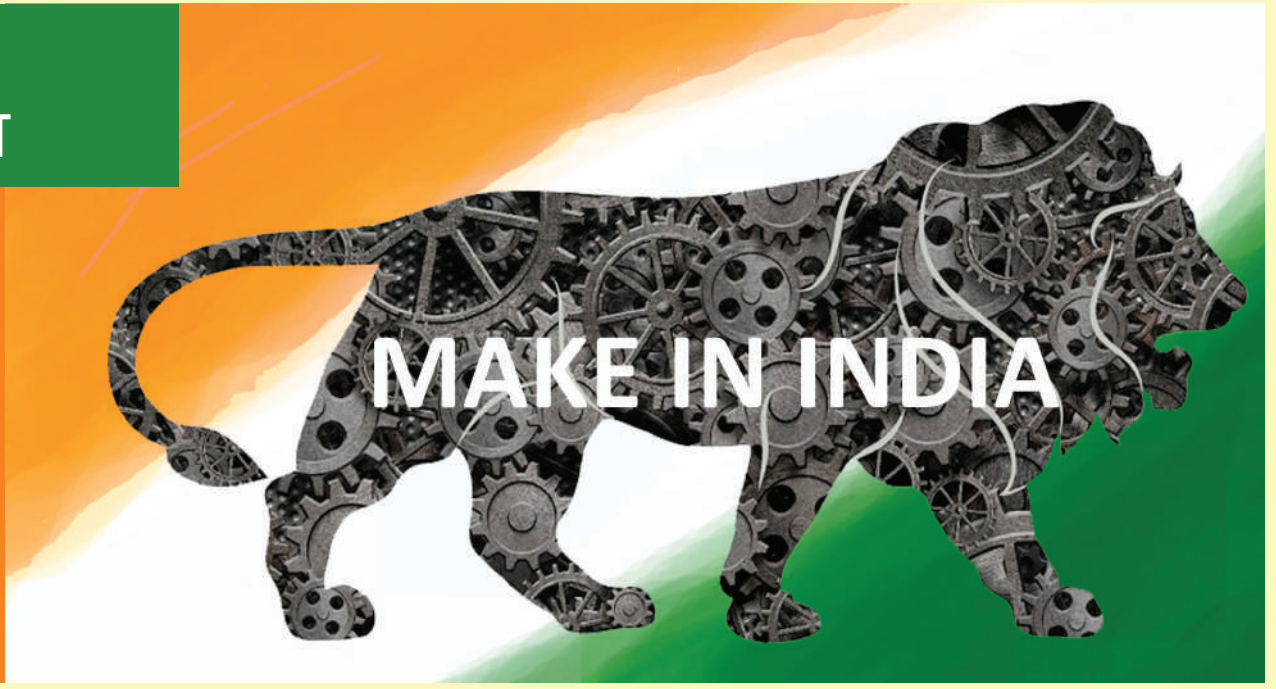

आयुध नियमावली, 2016 अधिसूचित की गई

आयुध और गोला बारूद के निर्माण के क्षेत्र में ''मेक इन इंडिया'' को बढ़ावा देने और ''ईज़ ऑफ़ डूइंग बिजनेस'' में सुविधा के लिए

आयुध नियमावली को और सरल बनाया गया:

आयुध और गोला बारूद निर्माण और हथियार प्रणाली में निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए

लाइसेंस

लाइसेंस शुल्क को युक्तिसंगत बनाया गया है और लाइसेंसधारी कम्पनी को निर्माण के लिए स्वीकृत लाइसेंस अब लाइफ़ टाइम के लिए वैध माने जाएंगे

निवेश के लिए प्रस्ताव

राष्ट्रीय सुरक्षा दृष्टिकोण से गृह मंत्रालय ने पिछले 04 वर्षों के दौरान 4000 से अधिक निवेश के प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की

विदेशियों को सुविधा प्रदान करना

भारतीय मूल के **व्यक्ति** > जनवरी 2015 में **विलय की गई** < भारत के विदेशी **नागरिक**

कार्ड स्कीम — कार्ड स्कीम

165 देशों के नागरिकों के लिए ई–वीज़ा की सुविधा। ई–वीज़ा की अवधि 30 दिन से बढ़ाकर 60 दिन की गई। विदेशी पर्यटकों की संख्या 2014 में 70 लाख से बढ़कर 2017 में 1 करोड़ हुई

डबल एंट्री

ई–टूरिस्ट एवं ई–बिज़नेस वीज़ा के लिए शुरू की गई

अवधि

165 देशों के नागरिकों के लिए डिफॉल्ट ऑप्शन के रूप में नियमित टूरिस्ट तथा बिज़नेस वीज़ा की अवधि 05 वर्ष कर दी गई

भारतीय नागरिकता हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से ऑनलाइन बनाया गया। इंदौर में फ्लेगशिप परियोजना के रूप में ऐसे आवेदनों पर ऑनलाइन प्रक्रिया आरम्भ की गई

मेडिकल वीज़ा की अनुमति 165 देशों के नागरिकों के लिए डिफॉल्टर ऑप्शन के रूप में ट्रिपल एंट्री के साथ 06 माह के लिए प्रदान की गई

- स्थानीय रेज़ीडेंट स्टेटस योजना (पीआरएस): एक निश्चित निवेश सीमा से ऊपर विदेशी निवेशकों के लिए अक्टूबर 2016 से शुरू की गई

- वीज़ा की सुविधाः विदेश स्थित भारतीय शरणार्थियों तथा व्युत्पन्न शरणार्थियों अर्थात पति/पत्नी और बच्चों के लिए

- पांच वर्षीय मल्टीपल ऐंट्री टूरिस्ट वीज़ाः बांग्लादेश के मुक्ति योद्धाओं के लिए अनुमति दी गई

- वीज़ा रेजीम अब टूरिज़्म वीज़ा को किसी भी प्रकार के वीज़ा के साथ क्लब करने, विश्व में कहीं से भी रोजगार एवं कारोबारी वीज़ा के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करता है तथा छोटी अवधि तथा लम्बी अवधि के वीज़ा के सह-अस्तित्व की अनुमति देता है

- ई-सर्विस मॉड्यूल का शुभारम्भ किया गयाः अप्रैल 2018 से भारत में रह रहे विदेशियों के लिए सभी एफआरआरओ में 27 सेवाएँ प्रदान करने हेतु

- प्रोटेक्टिड एरिया परमिट (पीएपी): मणिपुर, मिज़ोरम तथा नागालैण्ड में पीएपी व्यवस्था में छूट को 31.12.2022 तक बढ़ाया गया

- पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान एवं बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के धार्मिक उत्पीड़न के शिकार हिंदुओं, सिक्खों, बौद्धों, जैनों, पारसियों, ईसाईयों के प्रवेश एवं प्रवास (जिन्होंने 31.12.2014 तक भारत में प्रवेश किया था) को कानूनी बनाया गया

विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) को चुस्त-दुरुस्त बनाना

- यूजर फ्रेंडली एक नया एफसीआरए वेब पोर्टल शुरू किया गया
- एफसीआरए के अंतर्गत सभी सेवाओं जैसे पंजीकरण, पूर्व अनुमति, पंजीकरण का नवीकरण, ब्यौरे में परिवर्तन, विदेशी आतिथ्य को ऑनलाइन किया गया
- एफसीआरए 2010 के अंतर्गत सेवाओं का लाभ उठाने के लिए नीति आयोग के दर्पण पोर्टल के अंतर्गत यूनिक आईडी को अनिवार्य बनाया गया
- नवीकरण के लिए 2000 से अधिक ऑनलाइन आवेदनों पर कार्रवाई की गई
- 57 बैंकों को पीएफएमएस से जोड़ा गया और इसमें 99 प्रतिशत एफसीआरए बैंक खातों को कवर किया गया
- लगभग 19000 निष्क्रिय-नॉन-कम्प्लाएंट एसोसिएशनों के पंजीकरण को कानून की सम्यक प्रक्रिया को अपनाते हुए रद्द किया गया

साम्प्रदायिक सौहार्द

- नेशनल फाउन्डेशन फॉर कम्यूनल हार्मोनी की जनरल बॉडी, गवर्निंग काउन्सिल एवं एक्सक्यूटिव काउन्सिल को पुनर्गठित किया गया तथा उनकी बैठकें आयोजित की गईं

- साम्प्रदायिक सौहार्द पुरस्कार के लिए संगठनों एवं व्यक्तियों के चयन हेतु भारत के उपराष्ट्रपति की अध्यक्षता में निर्णायक मंडल (ज्यूरी) गठित किया गया

पद्म पुरस्कार

- चयन प्रक्रिया को पूर्ण रूप से बदल दिया गया है
- अब सभी नागरिकों के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया सुलभ है
- चार वर्ष पूर्व प्राप्त हुए 1800 नामांकनों के मुकाबले वर्ष 2018 में 36000 नामांकन प्राप्त हुए हैं

कुछ पुरस्कार विजेताः पद्म विभूषण

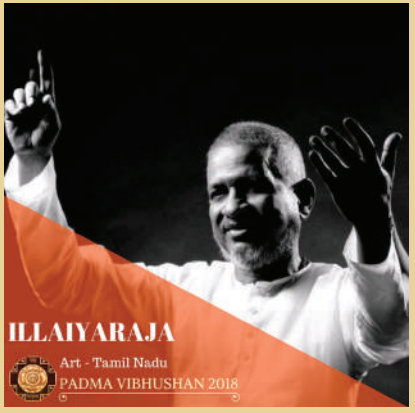

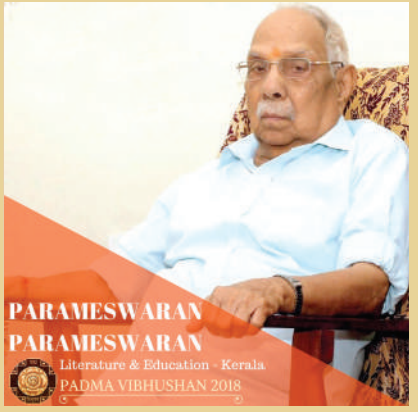

कुछ पुरस्कार विजेताः पद्म भूषण

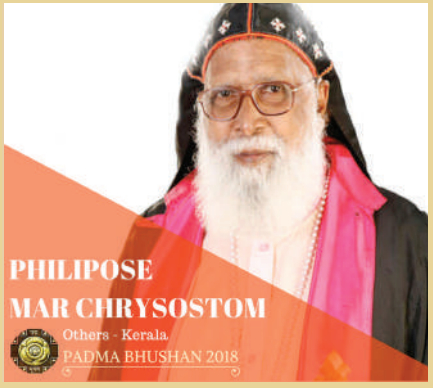

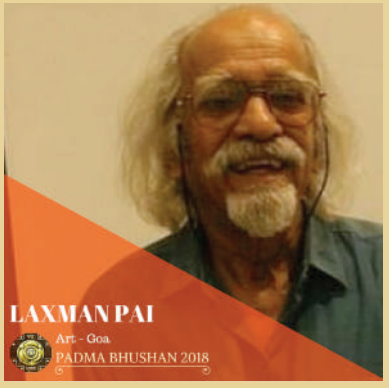

गुमनाम नायक

- कई गुमनाम नायकों को उनकी प्रतिभा और समाज के प्रति निःस्वार्थ सेवा के लिए पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किए गए

रोमुलस विटेकर
वन्य जीव संरक्षण

सुभाषिनी मिस्त्री
सामाजिक कार्य

लेंटिना ऐओ ठक्कर
सामाजिक कार्य

लक्ष्मी कुट्टी
हर्बल मेडिसन

श्री भज्जूस श्याम
कला एवं गोंड पेंटिंग

अरविन्द गुप्ता
साहित्य एवं शिक्षा

केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस बल के जवानों के परिवारों के साथ

“आत्म बोध का सर्वोत्तम तरीका स्वयं
को दूसरों की सेवा में समर्पित कर देना है”

महात्मा गांधी

2 अक्तूबर 1869 – 30 जनवरी 1948